बैंकों के लिए भी वित्तीय समावेशन बेहतर है

साभार: बिजनेस लाइन
(04 नवंबर, 2017)

एम मुस्ताक अहमद (प्रोफेसर, ससेक्स विश्वविद्यालय)
सुशांता के मल्लिक (प्रोफेसर, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

यह बैंकों को जोखिम रहित बनाता है, सस्ते खुदरा जमा राशि में मदद करता है, अस्थिरता पर निर्भरता को कम करता है, महंगी मुद्रा बाजार में वित्तपोषण की समस्या को दूर करता है।

वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति प्राथमिकता होने के बावजूद, यह वित्तीय सेवाओं के प्रदाताओं की सुदृढ़ता पर कैसे प्रभाव डालता है, इसके संबंध में हम बहुत कम जानते हैं। बैंकों के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नमूने का उपयोग करते हुए हम पाते हैं कि बैंकों के स्थिरता में वित्तीय समावेशन का एक उच्च स्तर से अधिक योगदान होता है।

यह संबंध विशेष रूप से उन बैंकों के लिए है, जिनके पास उच्च ग्राहक जमा राशि का हिस्सा है और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की कम सीमांत लागत है और उन बैंकों के लिए भी है जो मजबूत संस्थागत गुणवत्ता वाले देशों में काम करते हैं।

वित्तीय समावेशन, अर्थात, सभी आर्थिक एजेंट औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बना सके और ऐसी सेवाओं का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सके। हाल ही में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति प्राथमिकता बन गई है।

क्या लाभ हैं: मौजूदा स्थिति से पता चलता है कि वित्त तक अधिक से अधिक पहुंच से बचत बढ़ जाती है, आय असमानता और गरीबी को कम करती है, रोजगार बढ़ती है और समग्र कल्याण में सुधार होता है। सकारात्मक प्रभाव के बावजूद, बैंकों की सुदृढ़ता पर समग्रता के प्रभाव के बारे में बहुत कम जानकारी है, चूंकि बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था में परिवारों/फर्मों के लिए वित्तीय सेवाओं की थोक उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए इसकी एक स्पष्ट समझ समग्र वित्तीय विकास और विकास के लिए विशाल प्रबंधकीय और आर्थिक महत्व को बढ़ावा देता है। नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, बैंक बड़ी संख्या में ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, संभावित रूप से कम लागत पर और बड़े गैर-थोक दीर्घकालिक वित्तपोषण ला सकते हैं।

मौजूदा समीक्षा का सुझाव है कि खुदरा जमा निष्क्रिय, सस्ते और थोक वित्तपोषण की तुलना में जोखिमों पर असंवेदनशील है। इसलिए, एक समावेशी वित्तीय क्षेत्र में, बैंकों के पास विशाल ग्राहक आधार से जमा राशि की एक बड़ी राशि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवसर हैं, जिससे उन्हें धन की लागत और जोखिम कम करने में सक्षम होना चाहिए और इस तरह से ये और अधिक स्थिर हो जाएंगे।

हाल के समीक्षा से यह भी पता चलता है कि वित्तीय संस्थानों को ग्राहक की गुणवत्ता के बारे में सटीक संकेत मिलते हैं, जब उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। बढ़ी हुई बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच ने दूरी को कम करने में मदद की है जिससे वित्तीय संस्थानों को अच्छे रिश्ते बनाने में मदद मिलती है। बेहतर जानकारी के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ, बैंक नैतिक खतरों और प्रतिकूल चयन समस्याओं को कम करते हुए, न्यायिक उधार देने के फैसले और मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए, एक समावेशी वित्तीय क्षेत्र में कम सीमांत लागत वाले बैंकों को अत्यधिक जोखिम उठाने और अधिक स्थिर होने में सक्षम होना चाहिए।

वित्तीय समावेशन के लाभों को देखते हुए, बैंक एक समावेशी वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हैं और एक मजबूत संस्थागत गुणवत्ता के साथ वित्तीय मध्यस्थता में अधिक परिचालन दक्षता का अनुभव कर सकता है।

अधिक वित्तीय समावेशन के परिणामस्वरूप कई लाभ होने के बावजूद, हम यह भी मानते हैं कि एक समावेशी वित्तीय क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। गरीब परिवारों या छोटी कंपनियों से निपटने के दौरान ये सूचनात्मक असंपत्ति के कारण बैंकिंग स्थिरता के नुकसान के साथ जुड़ा हो सकता है। प्रबंधकीय और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी और जटिल संगठनात्मक और उत्पाद संरचना से जुड़ी एजेंसी की समस्याओं, जो एक व्यापक ग्राहक आधार प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है, के कारण यह भी हो सकता है। इसलिए हम तर्क देते हैं कि लाभ अधिक वित्तीय समावेश के साथ जुड़े लागतों से अधिक हो सकता है।

बैंक स्थिरता पर प्रभाव: वित्तीय समावेशन और बैंक स्थिरता के बीच के लिंक पर ठोस सबूत की अनुपस्थिति में, हमने 2004-2012 की अवधि के दौरान 86 देशों के 2,635 बैंकों के अंतरराष्ट्रीय नमूने का उपयोग करते हुए पाया है कि कैसे वित्तीय समावेश को बैंक स्तर की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

लेखक ने इस आलेख में बताया कि इन्होने पहले देश स्तरीय वित्तीय समावेश के समग्र सूचकांक का निर्माण करने के लिए वित्तीय आउटरीच और उपयोग आयाम का उपयोग किया था और फिर इन्होने बैंक और देश-विशिष्ट विशेषताओं के एक सारणी के लिए नियंत्रित करते हुए क्रॉस-कंट्री विश्लेषण में बैंक-स्तरीय स्थिरता पर प्रभाव देखने के लिए सूचकांक और उसके संबंधित आयाम दोनों को संबद्ध किया।

मुख्य निष्कर्ष: हमारा परिणाम यह संकेत देता हैं कि वित्तीय समावेश और बैंक स्थिरता के बीच मजबूत सहयोग है। विशेष रूप से, वित्तीय समावेशन की उच्च डिग्री, जोखिम को कम करने के मामले में बैंकों के प्रदर्शन को बेहतर करना है। व्यक्तिगत आयाम लेना, हमें वित्तीय आउटरीच / उपयोग और बैंक स्थिरता के बीच एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण संबंध भी मिला है।

इसके अलावा, हमने संभावित चैनलों का पता लगाया जिसके माध्यम से वित्तीय समावेशन बैंक की सुदृढ़ता को प्रभावित करती है। हमने पाया है कि एक समावेशी वित्तीय क्षेत्र में, जिन बैंकों में उच्च ग्राहक जमा धनराशि का हिस्सा है, वित्तीय सेवाओं का उत्पादन कम सीमांत लागत और जो मजबूत संस्थागत गुणवत्ता वाले देशों में कार्य करते हैं, वे अधिक स्थिर हैं।

नीति क्रियान्वयन: एक अंतरराष्ट्रीय नमूना का उपयोग करते हुए, हम व्यापक अनुभवजन्य प्रमाण प्रदान करते हैं कि अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन व्यक्तिगत बैंक स्थिरता के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। इस अध्ययन में, हमने पहली बार उन चैनलों की पहचान की है, जिसके माध्यम से वित्तीय समावेशन से बैंकों की सुदृढ़ता पर प्रभाव पड़ता है। इन परिणामों से यह संकेत मिलता है कि बैंक

जोखिम-मुक्त और अधिकतर सस्ते खुदरा जमाओं के पास पर्याप्त मात्रा में लाभ लेने के लिए एक तंत्र के रूप में वित्तीय समावेशन मानते हैं, जिससे निष्क्रियता और अक्सर महंगी मनी मार्केट फंडिंग पर निर्भरता कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण छूट प्रदान की जाती है।

वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी उत्पादन के उत्पादन की सीमांत लागत को कम करने के लिए एक उपकरण के रूप में भी काम करती है, जो बैंकों की अधिक मूल्य निर्धारण क्षमता में योगदान करती है और उन्हें अधिक स्थिर बनाती है। जितना अधिक वित्तीय समावेशीकरण स्थिर सामाजिक-राजनीतिक वातावरण को बढ़ावा देता है, उतना अधिक बैंकों के एक समावेशी वित्तीय क्षेत्र में सक्रियता बढ़ती हैं और उच्च स्तर की संस्थागत गुणवत्ता वाले देशों की स्थिरता में सुधार हो सकता है, क्योंकि वे उन सेटिंग्स में कुशलता से काम करते हैं।

हमारे परिणामों में महत्वपूर्ण नीति निहितार्थ हैं। गैर-बैंकिंग और/या गैर-बैंकिंग लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को व्यापक बनाते हुए बैंक प्रबंधक न केवल ग्राहकों की अप्रयुक्त क्षमता का फायदा उठाने और एक लॉक-इन प्रभाव पैदा करने का जल्दी फायदा उठा सकते है, बल्कि अधिक उत्पादक क्षेत्रों में संसाधनों को आवंटित करते समय एक समावेशी विकास एजेंडे को भी बढ़ावा दे सकते हैं।

संबंधित तथ्य

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1980 और 1990 के दशकों में शुरू किये गए ढाँचागत समायोजन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप हुए वित्तीय सुधारों का लाभ अनेक विकासशील देशों को भी मिला।
- यदि भारत के संबंध में बात करें तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में केवल एक बीमा कंपनी (जो जीवन बीमा एवं कुछ साधारण बीमा योजनाओं का संचालन करती थी) और एक स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत थे।
- परंतु अब यह दृश्य बदल गया है, वर्तमान में देश में 20 से अधिक बैंक, अनेक बीमा कंपनियाँ तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ-साथ कई प्रकार के वित्तीय संस्थान कार्यरत हैं। वस्तुत: इसका मूल कारण आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप हुआ देश का वित्तीय समावेशी विकास है।
- हालाँकि, वित्तीय समावेशन के विषय में यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि इसका कार्यक्षेत्र केवल बैंकिंग सेवाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बीमा, इक्विटी उत्पादों और पेंशन उत्पादों आदि विभिन्न प्रकार के वित्तीय सेवाओं के संबंध में भी समान रूप से लागू होता है।
- स्पष्ट रूप से वित्तीय समावेशन का अर्थ, बैंकिंग सेवा से वंचित किसी भी क्षेत्र में स्थित बैंक शाखा में केवल एक बैंक खाता खोलना मात्र कतई नहीं है।

वित्तीय समावेशन के अभाव से उत्पन्न चुनौतियाँ

- किसी व्यवस्था में वित्तीय समावेशन का अभाव होना समाज एवं व्यक्ति दोनों के लिये हानिकारक होता है।
- जहाँ तक व्यक्ति का संबंध है, वित्तीय समावेशन के अभाव में बैंकों की सुविधा से वंचित लोग मजबूरीवश अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिये बाध्य हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में ब्याज की दरें भी अधिक होती हैं और उधार दी गई राशि की मात्रा भी काफी कम होती है।
- चूँकि अनौपचारिक बैंकिंग ढाँचा कानून की परिधि से बाहर होता है, अत: उधार देने वालों और उधार लेने वालों के बीच उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का कानूनी तरीके से निपटान नहीं किया जा सकता है।
- इसके इतर जहाँ तक सवाल है वित्तीय समावेशन के सामाजिक लाभों का, तो आपको बताते चलें कि वित्तीय समावेशन के परिणामस्वरूप न केवल उपलब्धि बचत राशि में वृद्धि होती है, बल्कि वित्तीय मध्यस्थता की दक्षता में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं नित नए व्यावसायिक अवसरों को प्राप्त करने की सुविधा भी प्राप्त होती है।
- इस परिस्थिति में सरकार द्वारा प्रायोजित सर्वसुलभ बैंकिंग प्रणाली के परिणामस्वरूप अधिक प्रतिस्परर्धी बैंकिंग परिवेश की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विविधीकरण में योगदान प्राप्त हुआ है।

लाभ?

- आम आदमी को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल किये जाने से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत से लाभ भी प्राप्त होते हैं।
- जहाँ एक ओर इससे समाज में कमजोर तबके के लोगों को उनकी जरूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिये धन की बचत करने, विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे - बैंकिंग सेवाओं, बीमा और पेंशन उत्पादों आदि में भाग लेकर देश के आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
- वहीं दूसरी ओर इससे देश को पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होती है।
- इसके फलस्वरूप होने वाले धन के प्रवाह से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों को भी संवर्धन प्राप्त होता है।
- इसके अतिरिक्त वे लोग जो वित्तीय दृष्टि से विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए हैं, प्राय: अपनी बचत अथवा निवेश को भूमि, भवन अथवा गहनें आदि जैसी अनुत्पादक आस्तियों में लगाते हैं।
- जबकि वित्तीय दृष्टि से अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल लोग ऋण सुविधाओं का आसानी से उपयोग कर पाते हैं, फिर चाहे वे संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हों अथवा असंगठित क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में रहते हों अथवा ग्रामीण क्षेत्र में।
- वित्तीय समावेशन से सरकार को सरकारी सब्सिडी तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों में अंतराल एवं हेरा-फेरी पर रोक लगाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इससे सरकार उत्पादों पर सब्सिडी देने के बजाय सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर सकती है।

संभावित प्रश्न

सरकार वित्तीय प्रणाली में प्रत्येक परिवार के समावेशन के लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, ऐसा करने का एकमात्र उद्देश्य विकास से प्राप्त लाभों को जन-जन तक पहुँचाना है। इस कथन के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा इस दिशा में संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिये। (200 शब्द)

The government is fully committed to the goal of the inclusion of every person's family in the financial system, the only purpose of doing this is to bring the benefits received from development to the masses. In the context of this statement, give a brief description of the programs and schemes operated by the Government of India in this direction. (200 words)